इग्नू
जन–जन का
विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ

BSOC - 105
राजनीतिक समाजशास्त्र

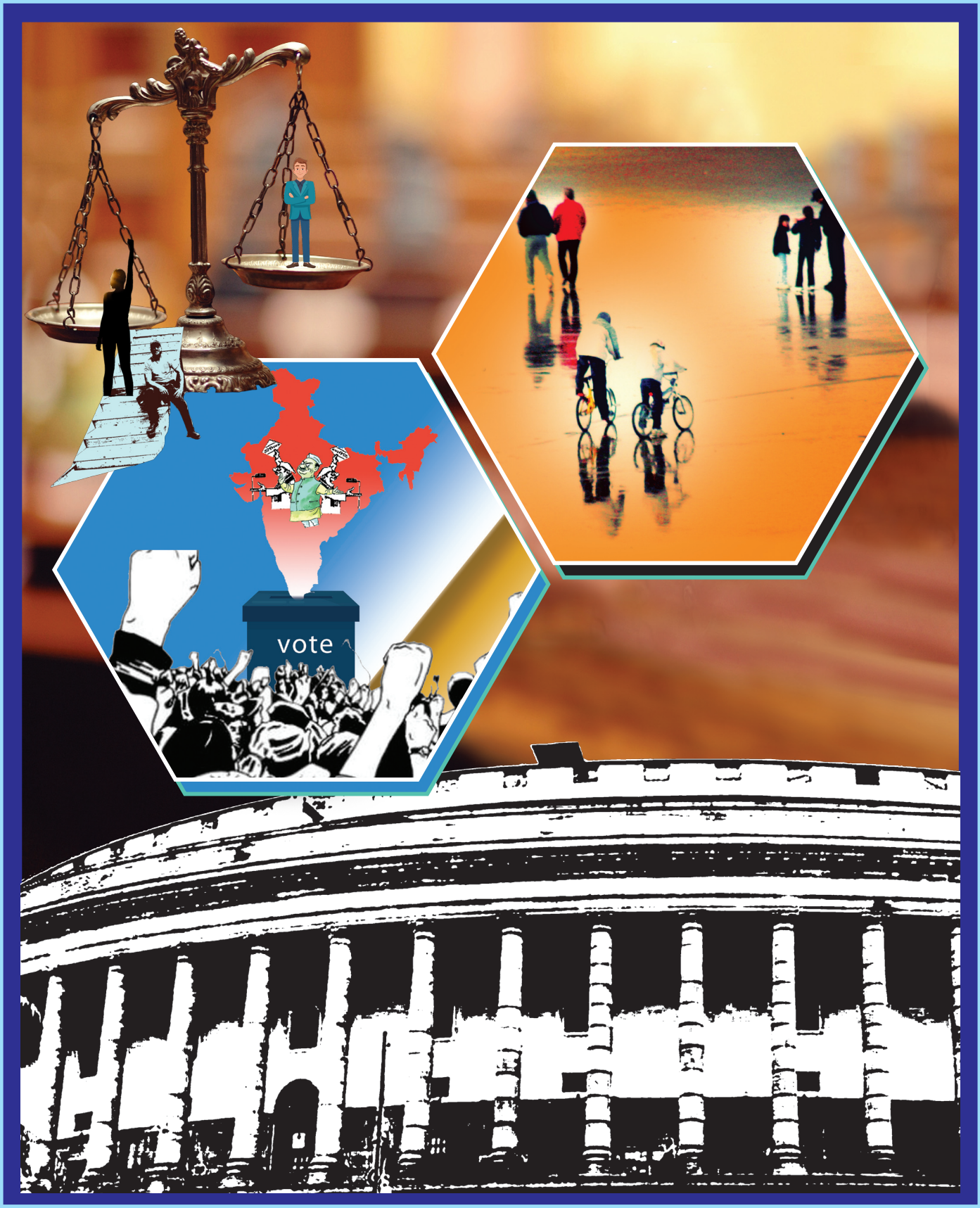

इग्नू
जन-जन का
विश्वविद्यालय
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ

BSOC- 105

राजनीतिक समाजशास्त्र

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ,
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

विशेषज्ञ समिति

प्रो. शरित भौमिक
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईसेस, मुम्बई

प्रो. डी.आर. साहू
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ. एस. श्रीनिवास रॉव,
जॉकिर हुसैन सेन्टर फॉर एडुकेशन स्टडीज,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. विभा अरोड़ा
आई.आई.टी. दिल्ली

डॉ. रीमा भाटिया
मिराण्डा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. परवेज अब्बासी
दक्षिण गुजरात विश्वविद्याल, सूरत, गुजरात

प्रो. स्वाति शिरोडकर, पूणे

प्रो. सुजाता,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

प्रो. देबल के. सिंहारॉय
समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. टी. कपूर
समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. नीता माथुर
समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. रवीन्द्र कुमार
समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. अर्चना सिंह
समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. किरनमई भूशी
समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. आर. वाशुम
समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम समन्वयक

प्रो. रवीन्द्र कुमार,
समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम संपादक

प्रो. रवीन्द्र कुमार,
समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम निर्माण दल

खंड/इकाई	शीर्षक	लेखक
खंड 1	**राजनीतिक समाजशास्त्र की समझ**	
इकाई 1	राज्यतंत्र और समाज	डॉ. विनोद आर्या, पंजाब केन्द्रीय विश्व विद्यालय, भटिंडा
इकाई 2	राजनैतिक समाजशास्त्रः प्रकृति और क्षेत्र	डॉ. विनोद कुमार यादव कंसलटैन्ट, समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू
खंड 2	**प्रमुख अवधारणाएँ**	
इकाई 3	राज्य और नागरिकता	डॉ. महिमा नायर स्वतंत्र शोधकर्ता, सिलवासा, दादर एवं नागर हवेली
इकाई 4	सत्ता और प्राधिकार	प्रो. रवीन्द्र कुमार समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली
इकाई 5	शासन, सरकार और शासकीयता	डॉ. महिमा नायर स्वतंत्र शोधकर्ता, सिलवासा, दादर एवं नागर हवेली
इकाई 6	अभिजन, शासन वर्ग और जनसमूह	गीतांजली अतरी शोधछात्र, सी.एस.एस.एस.,सामाजिक विद्यापीठ, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
खंड 3	**राजनैतिक प्रणाली**	
इकाई 7	खंडीय प्रणाली	प्रो. रवीन्द्र कुमार समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली
इकाई 8	सर्वसत्तावाद	प्रो. मानीषा पाण्डेय त्रिपाठी समाजशास्त्र विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली
इकाई 9	लोकतांत्रिक	प्रो. रवीन्द्र कुमार समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली
खंड 4	**रोजमर्रा में राज्य और सत्ता की स्थानीय संरचना**	
इकाई 10	भारत में राज्य और समाज	प्रो. रवीन्द्र कुमार समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

इकाई 11	स्थानीय स्वशासन	डॉ. करूणाकर सिंह राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
इकाई 12	सामाजिक आंदोलन और प्रतिरोध	डॉ. करूणाकर सिंह राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

सामग्री निर्माण

श्री तिलक राज सहायक कुलसचिव (प्रकाशन) इग्नू, एमपीडीडी	श्री यशपाल अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन) इग्नू, एमपीडीडी

फरवरी, 2021

© ***इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 20***

ISBN :

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के किसी भी अंश को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफी (चक्र मुद्रण) द्वारा अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी नई दिल्ली–110068 से अथवा इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव, एमपीडीडी द्वारा मुद्रित और प्रकाशित।

लेजर टाइप सेट एवं मुद्रण – गीता ऑफसेट प्रिंटर्स प्रा. लि., सी–90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–1, नई दिल्ली–20

विवरणिका

		पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		
खंड 1	**राजनीतिक समाजशास्त्र की समझ**	**7**
इकाई 1	राज्यतंत्र और समाज	9
इकाई 2	राजनीतिक समाजशास्त्रः प्रकृति और क्षेत्र	21
खंड 2	**प्रमुख अवधारणाएँ**	**31**
इकाई 3	राज्य और नागरिकता	33
इकाई 4	शक्ति और प्राधिकार	44
इकाई 5	शासन, सरकार और शासकीयता	58
इकाई 6	अभिजन, शासन वर्ग और जनसमूह	69
खंड 3	**राजनैतिक प्रणाली**	**87**
इकाई 7	खंडीय प्रणाली	89
इकाई 8	सर्वसत्तावाद	107
इकाई 9	लोकतांत्रिक	124
खंड 4	**रोजमर्रा में राज्य और सत्ता की स्थानीय संरचना**	**143**
इकाई 10	भारत में राज्य और समाज	144
इकाई 11	स्थानीय स्वशासन	158
इकाई 12	सामाजिक आंदोलन और प्रतिरोध	173

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

पाठ्यक्रम प्रस्तावना

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को समकालीन राजनैतिक मुद्दों का विवरण देते हुए राजनीतिक समाजशास्त्र में कुछ प्रमुख सैद्धांतिक बहस और अवधारणाओं से परिचित कराना है। इस पाठ्यक्रम का प्रमुख जोर राजनीतिक संबंधों की तुलनात्मक समझ विकसित करने की है, जैसे कि सत्ता, शासन और राज्य और समाज संबंधी पाठ्यक्रम को चार शीर्षकों में विभाजित किया गया है। जिसे हम खण्ड कहते हैं। प्रत्येक खंड राजनीतिक समाजशास्त्र के एक निश्चित पहलू को संबोधित करता है।

खंड 1 : राजनीतिक समाजशास्त्र की समझ दो इकाईयों में विभाजित है। इस खण्ड की इकाई 1 में राज्यतंत्र और समाज है, जो राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र (डोमेन) और राजनीति और समाज के बीच के संबंध को दर्शाता है। इकाई 2 राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र से संबंधित है। हम राजनीतिक समाजशास्त्र की उदय, राजनीतिक समाजशास्त्र की परस्पर विरोधी धारणाओं और राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र पर चर्चा करते हैं।

खंड 2 : मौलिक अवधारणाओं में राजनीतिक समाजशास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं का चर्चा है। इकाई 3 में, हम राज्य और नागरिकता की अवधारणाओं का अवलोकन करते हैं। हम उन तरीकों को खोजते हैं, जिनमें राज्य को ऐतिहासिक रूप से समझा गया है और यह उसके नागरिकों के साथ अपने संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि नागरिकता और अधिकारों की समझ नागरिकों की राज्य की बदलती भूमिका के साथ बदल जाती है। इकाई 4 में, आप शक्ति और प्राधिकरण की अवधारणा को समझते हैं। इकाई 5 में, हम सरकार शासन एवं शासकीयता की चर्चा करते हैं। हम सरकार, शासन और शासन के बीच अंतर्संबंधों को देखते हैं। इकाई 6 में हम अभिजन, शासक वर्ग और जनसमूह की चर्चा करते हैं। हम अभिजन और जनतासमूह के बीच अंतर को इंगित करके इस इकाई को शुरू करते हैं। फिर हम विभिन्न प्रकार के अभिजनों और संस्कृति, सामाजिक नेटवर्क और ज्ञान की भूमिका पर चर्चा करते हैं। फिर हम कुलीनों के पुनर्रूत्पादन में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका की व्याख्या करेंगे।

खंड 3 : राजनीतिक प्रणाली तीन इकाइयों से संबंधित है। इस इकाई 7 में आप राजनीति और राजनीतिक संगठन के बारे में जानने वाले हैं। आप उन खण्डीय प्रणाली के बारे में सीखते हैं, जिनमें आमतौर पर एक केंद्रीकृत प्रणाली का अभाव होता है। यहां राजनीतिक नियंत्रण के संबंध में नातेदारी संगठन के महत्व से संबंधित है। हमने यहां उस राजनीतिक प्रणाली पर चर्चा की है, जो खंडीय समाजों में मौजूद है। हमने भारत में खंडीय जनजातियों का भी वर्णन किया है। अंत में, हमने राज्यहीन समाजों में सरकार के उद्भव पर चर्चा की है। इकाई 8 में हम सर्वसत्तावादी राजनीतिक प्रणाली पर चर्चा करते हैं। हम इस इकाई को सर्वसत्तावादी सरकार के स्वरूप से शुरू करते हैं। फिर हम सर्वसत्तावादी (1919–1939), इटली में फासीवाद, जर्मनी में स्टालिन के सर्वसत्तावादी राज्य और नाजीवाद पर चर्चा करते हैं। इसके बाद हम सर्वसत्तावाद के प्रमुख लक्षणों पर चर्चा करते हैं। इकाई 9 में हम लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली और लोकतंत्र की अवधारणा के अर्थ और उद्भव की चर्चा करते हैं। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में कुछ तत्त्व शामिल होते हैं। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के इन तत्त्वों की व्याख्या करते हुए यह इकाई विचारधारा, संरचना और प्रकार्य, राजनीतिक प्रक्रियाओं और एक राजनीतिक प्रणाली की वैधता के आधार पर प्रकाश डालती है।

खंड 4 रोजमर्रा में राज्य और सत्ता की स्थानीय संरचना में तीन इकाईयां हैं। इकाई 10 में, हम तीन अंतर्संबंधित अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं। अर्थात् राष्ट्र, राज्य और समाज। फिर, हम इस सामान्य चर्चा को भारतीय राष्ट्र-राज्य के उद्भव से जोड़कर संबंधित करते हैं। हम भारत में राष्ट्र–निर्माण के कार्य से जुड़ी रणनीतियों और चुनौतियों की जाँच करते हैं। अंत में, अंतिम खंड राष्ट्रीय एकीकरण के मुद्दे से संबंधित है। इकाई 11 में किसी भी समाज में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे तंत्र के रूप में देखा जाता है, जो लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जा रहा है। स्थानीय शासन को समाज के सबसे निचले स्तरों पर संचालित किया जाता है। स्थानीय सरकार से स्व–शासन शब्द अधिक स्पष्ट रूप से अपने दैनिक कार्यों के निर्वहन में लोगों की भागीदारी की अवधारणा पर जोर देता है। इकाई 12 में हम सामाजिक आंदोलनों और प्रतिरोध के बीच की कड़ी पर चर्चा करते हैं। हम तब परिभाषित करते हैं कि सामाजिक आंदोलनों और विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन का महत्व क्या है। हम सामाजिक आंदोलनों और प्रतिरोध के बीच प्रतिरोध और अंतराफलक (इंटरफेस) पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं।

खंड

1

राजनीतिक समाजशास्त्र की समझ

इकाई 1
राज्यतन्त्र और समाज 9

इकाई 2
राजनीतिक समाजशास्त्रः प्रकृति और क्षेत्र 21

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 1 राज्यतन्त्र और समाज

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 राजनीतिक क्षेत्र

1.2.1 राजनीतिक प्रणाली क्या है?

1.2.2 शक्ति की धारणा

1.3 राजनीति और समाज

1.3.1 समाजशास्त्रीय अन्वेषण

1.3.2 मानवशास्त्रीय अन्वेषण

1.4 राज्य, राष्ट्र और समाज

1.5 समाज, नागरिकता और लोकतंत्र

1.6 वैश्वीकरण, राज्यतन्त्र और समाज

1.7 सारांश

1.8 उपयोगी पुस्तकें

1.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.10 शब्दावली

1.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप;

- राजनीतिक क्षेत्र को समझ सकेंगे;
- राजनीति और राज्यतन्त्र के बीच के अंतर को समझ सकेंगे;
- राज्य, राष्ट्र और समाज के बीच अंतर और उसे परिभाषित कर सकेंगे;
- समाज, नागरिकता और लोकतंत्र के बीच के संबंधों पर चर्चा कर सकेंगे;
- वैश्वीकरण, राजनीति और समाज के बीच अंतः संबंधों का वर्णन कर सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना

इस इकाई में, आप राज्यतन्त्र और समाज के बीच के संबंधों का अवलोकन करेंगे। इस इकाई में हम राज्यतन्त्र और समाज के समाजशास्त्रीय एवम् मानवशास्त्रीय अनुभवों पर भी चर्चा करेंगे। अगले भाग में, हम तीन अंतःसंबंधित अवधारणाओं अर्थात् राष्ट्र, राज्य और समाज पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम वैश्वीकरण, राज्यतन्त्र और समाज के बीच संबंधों को दर्शाएंगे।

* डा. विनोद आर्या द्वारा लिखित

आइए हम समाज में मनुष्यों के जीवन जीने के सामूहिक तरीकों के पीछे मूल कारणों का पता लगाने का प्रयास करें। अब तक आदिमानव (होमो सेपियन्स) के विकास के ज्ञात इतिहास के अनुसार – वे छोटे या बड़े समूहों में एक दूसरे के साथ क्यों रहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम कुछ ऐसे सिद्धांतो को पाएंगे जो इसके पीछे काम करने वाले कारणों की व्याख्या करते हैं। प्रारंभिक काल में शारीरिक समानताओं और जंगली जानवरों के भय के कारणों से आदिमानव ने छोटे समूह बनाए और इस अवस्था को शिकारी और एकत्रित समाज कहा जाता था।

लेकिन जैसे ही लोग समूहों में इकट्ठा हुए; समूह में अनुक्रम और व्यवस्था बनाने का सवाल उठा। दूसरे शब्दों में, समूह का नेतृत्व कौन करेगा और अधीनस्थ कौन होगा। इसे हम बल का सिद्धांत कह सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार; कमजोर लोगों पर शक्तिशाली लोगों द्वारा शासन किया गया। लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुँचना आसान नहीं था, कि कौन कमजोर है और कौन शक्तिशाली। अतः इस तरह की स्थिति युद्ध की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकती थी जिसमें सभी एक दुसरे के खिलाफ हों। ऐसी स्थिति से हमें बचाने के लिए थॉमस हॉब्स सामाजिक अनुबंध के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि सभी व्यक्तियों ने अंततः एक ऐसी स्थिति पर अपनी सहमति दे दी है जहां उन सभी ने अपनी कुछ स्वतंत्रता का त्याग कर दिया है; दूसरों के अधिकारों के निर्माण में अग्रणी होंगे और वे एक शासी निकाय द्वारा संरक्षित होंगे। सरल शब्दों में, लोगों ने समाज में प्रत्येक के खिलाफ युद्ध की स्थिति में नहीं रहने का फैसला किया; जहाँ कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता था, इसलिए वे दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण किये बिना एक दुसरे के साथ रहने के लिए सहमत हुए और इस व्यवस्था या सामाजिक अनुक्रम को शासक द्वारा अनुरक्षित रखा जाएगा। सत्तारूढ़ प्रणाली जो प्रारंभिक रूप में जाति या रक्त–संबंधी समूह के मुखिया, सामंती शासकों, छोटे क्षेत्रों के शासकों, साम्राज्यों (राजाओं के शासन), अभिजात वर्ग से शुरू हुई और धीरे–धीरे लोकतंत्रों के रूप में विकसित हुई।

इस प्रकार, हम अनुमान लगा सकते हैं कि, 'राज्य' एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो आज हमारे जीवन को व्यापक और बाहुल्य तरीकों से नियंत्रित करता है। इसके अलावा, 'राज्य' एक संस्था के रूप में – अनुक्रम की एक प्रणाली और शक्ति संबंध की एक संरचना का गठन करता है जो पूरे समाज को नियंत्रित और विनियमित करता है। दूसरी ओर समाज एक सामाजिक समूह है जो लोगों को सहयोग और उनके अस्तित्व के लिए उन्हें एक साथ बांधता है। लेकिन विभिन्न समाजों के रूप में ये सामाजिक समूह राज्य के संस्थागत तंत्र द्वारा शासित और रूपांतरित होते हैं। विभिन्न नियमों, विनियमन और शासन की प्रकृति के माध्यम से यह नागरिकता और सामाजिक व्यवस्था के रूप को आकार देता है। समाज और व्यक्ति राज्य और उसके विभिन्न चरित्रों से बहुत प्रभावित होते हैं। एक संस्था के रूप में, राज्य एक सुशक्तिशाली उपकरण बनने के लिए प्रयास करता है जो एक प्रकार की नागरिकता का निर्माण करता है। आइये अब हम राजनीतिक क्षेत्र पर चर्चा करते हैं।

1.2 राजनीतिक क्षेत्र

आइए हम अपने सामाजिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र को पहचाने। राज्यतन्त्र (पॉलिटी) शब्द ग्रीक भाषा के शब्द "पॉलिस" से लिया गया है, जिसका अर्थ है सरकार का एक अभ्रष्ट रूप, जिसमें कई लोग मिलकर जनता के आम हितों के लिए शासन करते हैं। अतः 'पॉलिटी' (राज्यतन्त्र) शब्द राजनीतिक प्रणाली से संबंधित है (बिली, 1999: 261)। इस उद्देश्य के लिए, हम सर्प्रथम इस बात की चर्चा करेंगे कि सामाजिक संबंध के शक्ति के

आयामों को एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है। तत्पश्चात, हम शक्ति शब्द के व्यापक और सीमित दोनों अर्थों पर विचार करेंगे।

1.2.1 राजनीतिक प्रणाली क्या है?

हम पाते हैं कि सामाजिक संबंधों को स्थापित करने के लिए लोग एक दूसरे के साथ संपर्क रखते हैं। ऐसा करने में, वे अक्सर अपने आत्महितों का अनुसरण करते हैं। ये आत्महित कभी–कभी दूसरों के हितों और समाज के हितों के लिए भी विपरीत कार्य करते हैं। अपने हितों की पूर्ति के लिए लोग शक्ति के साधनों का उपयोग करते हैं और दूसरों के हितों को नियंत्रित करते हैं। यह स्थिति निरपवाद रूप से संघर्ष की ओर ले जाती है। सामाजिक संबंधों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हमें संघर्ष को हल करने और लोगों की विविध गतिविधियों को समन्वित करने की आवश्यकता है। यह आमतौर पर शक्ति का प्रयोग करने और लोगों के व्यवहार पर कुछ प्रकार के प्रतिबंध आरोपित करके किया जाता है। जब सामाजिक संबंधों को शक्ति के आयाम के इर्द–गिर्द संघटित किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अब हम सामाजिक संपर्क के सामान्य क्षेत्र से हटकर शक्ति संबंधों के अधिक विशिष्ट क्षेत्र में आ गये हैं। जब शक्ति संबंधों को व्यवस्थित और विशिष्ट कार्यों के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, तो हम एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में इसकी बात करते हैं। अतः जब भी व्यक्ति और समूहों के बीच संबंध शक्ति और इसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों के व्यवहार के अनुसार सुनियोजित होते है तो राजनीतिक प्रणालियाँ विकसित होती हैं। ये साधारण समाजों में ग्राम के बुजुर्गों की छिटपुट बैठकों से लेकर उच्च संगठित राज्यों तक हो सकते हैं। उस विशिष्ट तरीके को समझने के लिए जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संचालित होती है, हमारे लिए यह उपयुक्त है कि हम पहले शक्ति की धारणा और सामान्यतः राजनीतिक प्रणाली की परिभाषा से इसके संबंध को समझें। इसके बाद हम इसके संबंधों को राष्ट्र–राज्यों के विशिष्ट मामले के साथ भी देख सकते हैं।

1.2.2 शक्ति की धारणा

शब्दकोष में दी गई शक्ति की परिभाषा के अनुसार, कुछ करने या कुछ भी करने या किसी व्यक्ति या वस्तु पर कार्य करने की क्षमता है। इस तरह से देखें, तो शक्ति सामाजिक विज्ञान में एक मूल अवधारणा है। इसका तात्पर्य उस प्रभाव से है, जो कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन दूसरों के कार्यों को वहन करने के लिए प्रयोग करता है। इस अर्थ में, दूसरों की प्रतिक्रिया को प्रकाश में लाकर हितों की पूर्ति का प्रयास करना किसी व्यक्ति द्वारा शक्ति का प्रयोग करने के रूप में वर्णित हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी के पास सामाजिक शक्ति है, जिसका उपयोग दूसरे व्यक्ति को वह सब करने का दबाव डालने के लिए किया जा सकता है जो वह दूसरे व्यक्ति से कटवाना चाहता है। यह सामाजिक शक्ति अनिवार्य रूप से अंतर्व्यक्तिगत संबंधों का एक पहलू है।

आइए देखें क्या होगा यदि हम राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए सामाजिक शक्ति का उपयोग एक मानदंड के रूप में करें। इसका अर्थ यह होगा कि राजनीति के क्षेत्र में लगभग सभी मानवीय कार्य और पारस्परिक क्रियाएं आएंगी। यह राजनीति की संभवतः सबसे व्यापक परिभाषा होगी। राजनीतिक वैज्ञानिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं। आइए देखें कि उनका क्या कहना है।

राजनीति के क्षेत्र का परिसीमनः राजनीतिक वैज्ञानिकों का तर्क है कि राजनीति का यह दृष्टिकोण इसे एक बहुत ही सामान्य स्थान और व्यापक विषय के स्तर तक कम कर देता है। इसलिए, वे राजनीति के क्षेत्र का परिसीमन करते हैं और 'राजनीति' शब्द को उस क्षेत्र

को लक्षित करने के लिए सुरक्षित रखते हैं, जहां सामाजिक शक्ति का उपयोग निजी क्षेत्र के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, सत्ता संबंधों के मामले में परिवार के भीतर क्या होता है, यह राजनीति की श्रेणी में शामिल नहीं है। जब परिवार या उसके प्रतिनिधि दूसरों के विचारों और कार्यों को प्रभावित करके पड़ोस या गांव के मामलों में भाग लेते हैं, तो इसे राजनीति के रूप में वर्णित किया जाता है। इस तरह से देखा गया है, शक्ति और इसकी विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, प्राधिकार, दबाव, बल आदि राजनीति पर चर्चा करने के लिए मान्य शब्द हैं।

प्राधिकरण की अवधारणा: राजनीतिक संबंधों के विशेष क्षेत्र को और अधिक परिसीमित करने के लिए, प्राधिकरण की अवधारणा को लागू करना उपयोगी होता है। यह शक्ति के उपयोग की वैधता को संदर्भित करता है। जब सार्वजनिक क्षेत्र में शक्ति संबंध नियमित हो जाते हैं, और इसलिए कुछ हद तक अनुमानित होते है, तो वे भी उचित मानदंडों द्वारा बारीकी से निर्देशित होते हैं। लोग सत्ता का प्रयोग करने के लिए राजनीतिक प्राधिकरण के अधिकार को स्वीकार करते हैं। इसका तात्पर्य राजनीतिक संस्थानों की स्वीकृति की एक स्पष्ट प्रणाली के अस्तित्व से है जिसके माध्यम से प्राधिकार या शक्ति के वैध उपयोग का प्रचलन होता है। दूसरे शब्दों में, शक्ति प्राधिकार बन जाती है क्योंकि इस संबंध में शामिल कर्ता आदेश जारी करने वालों की वैधता (कम या अधिक स्तर पर) स्वीकार करते हैं। वे स्वाभाविक रूप से पालन करने के लिए मजबूर नहीं हैं, वे स्वेच्छा से ऐसा करते हैं। इस तरह के व्यवस्थित राजनीतिक संबंधों को आमतौर पर राजनीतिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है।

राजनीति का अधिक सीमित दृष्टिकोण: राजनीति के एक और भी अधिक सीमित दृष्टिकोण को लेते हुए मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री राजनीतिक संबंधों को व्यक्तियों के संगठन तक सीमित कर देते हैं। उनके लिए, इस संगठन को क्षेत्रीय रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। दूसरे इसे भौतिक बल की अंतिम स्वीकार्यता पर आधारित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मैक्स वेबर राज्य की धारणा का उल्लेख उस रूप में करते हैं जैसा की यह आधुनिक अर्थों में उभरा है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संबंधों का वर्णन करने के उद्देश्य से, हमें राजनीति के इस प्रतिबंधित अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

लेकिन समाजशास्त्रियों के रूप में, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक संबंध उन समाजों में भी मौजूद हैं, जिनके पास राज्य जैसी विशिष्ट राजनीतिक संस्थान नहीं है। बड़ी संख्या में आदिवासी समाजों में, राजनीतिक प्राधिकार क्षेत्र पर आधारित नहीं है। उदाहरण के लिए, भारत में गुज्जर और यूरोप में रोमा या जिप्सी जैसे खानाबदोश जनजातियों के पास अपने पथभ्रष्ट सदस्यों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए, विवादित मामलों को निपटाने के लिए, अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए परिषदें हैं। आइए अब हम राज्य, राष्ट्र और समाज पर चर्चा करते हैं।

बोध प्रश्न 1

i) सामाजिक संबंधों की क्रमबद्ध व्यवस्था के लिए दो अनिवार्य आवश्यकताएं क्या हैं?

.....

.....

.....

ii) राजनीतिक प्रणाली क्या है?

.....

.....

.....

iii) राजनीति के संदर्भ में शक्ति और प्राधिकार को परिभाषित करें।

.....

.....

.....

iv) राजनीति का एक सीमित दृष्टिकोण है यह कहने से हमारा क्या तात्पर्य है?

.....

.....

.....

1.3 राज्य, राष्ट्र और समाज

आधुनिक समय में राजनीति पर चर्चा करते हुए, हम आम तौर पर राज्य, राष्ट्र और समाज की बात करते हैं। पश्चिमी यूरोपीय अनुभव के संदर्भ में, ये तीन शब्द कुछ हद तक समान हैं। अन्य कई स्थानों के मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम पहले इन पदों को परिभाषित करें।

i) **राज्यः** राज्य एक राजनीतिक संघ है, जो कि निम्न द्वारा चरितार्थ होता है

   क) प्रादेशिक क्षेत्राधिकार,

   ख) कम या अधिक गैर–स्वैच्छिक सदस्यता,

   ग) नियमों का एक समूह जो संविधान के माध्यम से उसके सदस्यों के अधिकारों को परिभाषित करता है और

   घ) अपने सदस्यों पर सत्ता की वैधता का दावा करता है।

किसी राज्य के सदस्य को आमतौर पर नागरिक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अधिकतर राज्य राष्ट्रीयता के समान/समानार्थी है।

ii) **राष्ट्रः** यह शब्द ऐसे लोगों के समूह को संदर्भित करता है, जिन्होंने संस्कृति, धर्म, भाषा और राज्य आदि की सामान्य पहचान के आधार पर एकजुटता विकसित की है। किसी भी समूह की राष्ट्रीय पहचान, जो स्वयं को इस तरह परिभाषित करती है, किसी भी मानदंड के आधार पर हो सकती है, जैसे निवास स्थान, जातीय मूल, संस्कृति, धर्म और भाषा।

iii) **समाजः** यह नातेदारी सामाजिक संगठन की सबसे व्यापक श्रेणी है जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं, जैसे नातेदारी, परिवार, अर्थव्यवस्था और राज्यतन्त्र। अर्थात, समाज शब्द का तात्पर्य सामाजिक संबंधों से है जो परस्पर जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ अन्तक्रियाएं करते हुए लोग सामाजिक संबंध बनाते हैं। सामाजिक संबंधों की पुनरावृत्ति और नियमित प्रतिमान संस्थागत हो जाते हैं और इसलिए एक संबंधपरक अवधारणा के रूप में समाज सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन शामिल करता है।

दूसरी ओर, एक तात्विक अवधारणा के रूप में समाज शब्द एक सामान्य शब्द है जो राज्य

या राष्ट्र को समाविष्ट कर सकता है। यह किसी एक या दोनों के साथ समान अर्थ में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जर्मन समाज में पूर्वी जर्मनी, पश्चिम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, स्विट्जरलैंड आदि के जर्मन भाषी लोग भी शामिल हो सकते हैं। एक और उदाहरण लें तो, हिंदू समाज में नेपाल, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हो सकते हैं।

राज्य में इसी तरह के कई समाज शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय राज्य में क्षेत्र, धर्म या भाषा के आधार पर विविध समाज शामिल हैं। आदिवासी समाज, जैसे कि भील, गोंड या नागा, भारतीय राज्य का एक अभिन्न अंग हैं। राज्य, राष्ट्र और समाज की अवधारणाओं पर चर्चा करने के बाद, आइए अब हम राज्यतन्त्र और समाज के समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय अन्वेषण पर चर्चा करते हैं। (ई इस ओ 12, ब्लोक 3, प 73–77)

बोध प्रश्न 2

i) समाज से क्या तात्पर्य है?

.....

.....

.....

ii) राष्ट्र क्या है?

.....

.....

.....

iii) राज्य की परिभाषा दीजिये। लगभग तीन पंक्ति में उत्तर दें।

.....

.....

.....

1.4 राजनीति और समाज

समाजशास्त्रीय अन्वेषण

समाज के भीतर राज्य की अवधारणा और इसकी भूमिका पश्चिमी दार्शनिक बहस के माध्यम से आती है, अरस्तू, प्लेटो, टोक्वेल (1835), अगस्त कोमटे (1851), मॉर्गन (1877) और हर्बर्ट स्पेंसर (1884) ने राज्य प्रणाली और समाज से इसके संबंध की खोज करने का प्रयास किया। इसके अलावा हॉबहाउस (1905), माइकल (1915), परेटो (1916), मैक्स वेबर (1922), मैनहेम (1935), पार्सन्स (1969) ने राज्यतन्त्र और समाज के संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका विश्लेषण समाज के उभरने और राज्य के साथ उसकी भूमिका को समझने के लिए एक स्रोत के रूप में काम करता है। समाज में राजनीतिक प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया और उसके अधिकारों के दावे का परिणाम है। ऐसी संस्था का निर्माण जो अपने नियमों और आदेशों को लागू करती है, राज्य की व्यवस्था समाज के विभिन्न वर्गों के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए बहुलता को बनाए रखती है। इस संदर्भ में, राज्य अक्सर समाज की एक इकाई के रूप में कार्य करता है, जिसके पास लोगों के अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। बाद में कार्ल मार्क्स ने समाज की राजनीतिक अर्थव्यवस्था तय करने के लिए राज्य की भूमिका पर जोर दिया।

"राज्य" शब्द संगठनों, कर्मियों, विनियमों और प्रथाओं के समूह को दर्शाता है जिसके माध्यम से एक क्षेत्र में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है (बोरगट्टा और मोंटगोमरीय 2000: 2996)। इसलिए, राज्यतन्त्र शक्ति संबंध और उसके प्रयोगों के रूप में उभरती है: आम लोगों की सेवा के लिए संसाधन जुटाना इसकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार, राज्य और राज्यतन्त्र का उद्देश्य कल्याण की धारणा को संरक्षित करना है और पूरे समाज को प्रगति और प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाना है। लेकिन इसमें विभिन्न रूचि, विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए समाज के भीतर यथासंभव स्थान बनाने के विशेषताएं हैं। समाज की प्रकृति अक्सर न केवल राजनीति की भूमिका निर्धारित करती है अपितु व्यापक रूप से आम जनता को भी प्रभावित करती है। मौटे तौर पर राज्य आम लोगों और समाज के हित को पूरा करने के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करता है। लेकिन आम तौर पर राजनीति की प्रकृति और लोगों की रुचि आपस में नहीं मिलती है। यह संघर्ष का कारण बन जाता है, इसलिए राज्य के प्रकार्य और इसके राज्यतन्त्र का कार्य लोगों की महत्वाकांक्षा के अंतर्गत आता है।

मानवशास्त्रीय अन्वेषण

राज्यतन्त्र और समाज के बीच संबंध मानवशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्रों के भीतर एक बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। मानवशास्त्र में अध्ययन राज्य और समाज से इसके संबंधो के पूर्व रूप का विश्लेषण करने के लिए बहुत हद तक व्यापक रहा है। मानवशास्त्रीय अध्ययनों के विषय में राज्यहीन समाज (उदाहरण के लिए इवांस प्रिचर्ड द्वारा अध्ययन किए गए नुएर्स समुदाय) के कई प्रमाण हैं जिसमें राजनीतिक प्रणाली का कार्य संगठित रूप में नहीं था। यह व्यक्तिनिष्ठ होने की बजाय वस्तुनिष्ठ रूप में था और सामाजिक संबंध और साझा सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर कार्य करता था। बाद में आधुनिक समाज का विकास राज्य और राष्ट्र राज्य की धारणा के एक रूप को सामने लाया। हॉब्स, लॉक और रूसो ने व्यक्तिनिष्ठ रूपों में समाज के भीतर समाज और सामाजिक संबंधों की आवश्यकता को समझने का प्रयास किया।

1.5 समाज, नागरिकता और लोकतंत्र

समाज उन लोगों से मिलकर बनता है जो मानदंडों और विनियमन के नियमों का पालन करते हुए संगठित रूप में एक साथ रहते हैं। जाति, धर्म, जातीयता के रूप में विभिन्न परंपराएं नागरिकता को आकार देती हैं। नागरिकता एक राज्य क्षेत्र के भीतर लोगों का एक राजनीतिक अधिकार है। राज्य विभिन्न नियमों और विनियमों के माध्यम से नागरिकता को नियंत्रित करके अपने लोगों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। लोकतंत्र की प्रकृति, जिसके भीतर आधुनिक विचार उभर कर सामने आया उसका निर्णय किसी विशेष राज्य के नागरिकों के रूप में भोगे जाने वाले व्यक्ति के अधिकारों के प्रकार द्वारा किया जाता है। समाज के विभिन्न संस्थानों में लोकतांत्रिक परंपरा अधिक मजबूती से अपनी जड़ें जमाए हुए है, अपने नागरिक को अधिकार देती हैं। राज्य अपनी नीतियों और कार्यक्रम के माध्यम से अक्सर बार–बार यह निर्धारित करते हैं कि किसी विशेष देश का नागरिक अपने जीवन और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों पर क्या अधिकार रखता है। लेकिन राजनीतिक स्तरों पर नागरिकता के कई आयाम हैं। हम देख सकते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार होने चाहिए, लेकिन विशेष क्षेत्र में रहने के लिए और विशेष क्षेत्र पर उनका दावा यह नहीं बताता है कि एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक गरिमापूर्ण जीवन का आनंद ले रहा है। उनकी नागरिकता सामाजिक स्थिति और उनकी संकल्प–शक्ति के उत्थान के लिए राज्य के हस्तक्षेप पर निर्भर है।

राजनीतिक संस्थाएं: मुद्दे और परिप्रेक्ष्य

राजव्यवस्था और समाज के बीच संबंधों को समझने के लिए, हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि कौन सा मुद्दा राजनीतिक संस्थानों को चरितार्थ करता है और उन्हें सामाजिक रूप से अधिक संवेदनशील बनाता है? भारत में गरीबी, जाति व्यवस्था, जातीयता, क्षेत्रीय प्रभाव और राजनीतिक संस्थानों जैसे विभिन्न मुद्दे हैं। समाज में शासन की समस्या को विभिन्न मुद्दों के साथ जोड़ा गया है। सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी, न्यायपालिका, न्याय देने के लिए नौकरशाही, संसाधनों और अवसरों में समानता एक बड़ी चुनौती रही है। उसी तरह, भारत में ऐसा समतावादी समाज बनाने के लिए जो विभिन्न रूढ़िवादी परंपराओं से बंधा है और आधुनिक तरीके से समस्या से निपटने के लिए आश्वस्त करना एक अन्य चुनौती है।

भारत में राजनीतिक संस्थानों ने कुछ हद तक मुद्दों को समझने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण का पालन किया। लेकिन भाई–भतीजावाद, भ्रष्टाचार ने राजनीतिक पार्टी को भ्रष्ट बना दिया है और वे समय के साथ लोगों के विश्वास को खोते जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप नीतियाँ भी विश्वास खोती जा रहीं है, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक दल गरीबी, उत्थान और रोजगार सृजन के बजाय जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि राजनीतिक संस्थान सामाजिक परिवर्तन के दीर्घकालिक मुद्दों जिन्हें एक वास्तविक प्रयास की आवश्यकता होती है उन पर ध्यान देने के बजाय परंपराओं से संबंधित सामाजिक मुद्दों पर अधिक ध्यान देते हैं।

भारत में सामाजिक मुद्दे और राज्यतन्त्र

भारतीय समाज प्रकृति में विविधतापूर्ण है। सामाजिक श्रेणियों के विभिन्न रूप सामाजिक असमानता के रूप में अंतर्निहित हैं। हम इसे जाति, वर्ग, लिंग और जातीयता में देख सकते हैं और विभिन्न समुदायों में रुचि की राजनीति में भी देख सकते हैं। राज्य अपनी नीति के माध्यम से असमानता और अभाव के सवाल का समाधान करने की कोशिश करता है।

भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है। यह पदानुक्रम और असमानता के वैचारिक सिद्धांतों पर आधारित है। भारतीय लोकतंत्र ने जाति आधारित असमानता और शोषण के रूप में, अपमान और अभावों के अन्य रूपों पर प्रश्न उठाने की प्रक्रिया को विकसित किया है। जाति का सवाल हमेशा सरकार के लिए एक चुनौती रहा है। चूँकि जाति का शोषणकारी चरित्रदृश्य की तुलना में अधिक अदृश्य है और भारतीय समाज में सैद्धांतिक रूप से इसे मान्यता देने के लिए शोषण के कई रूपों को पहचानना अभी बाकी है। समाज में कई सुधार हुए जिन्होंने जातिगत असमानता को संबोधित किया जैसे कि आरक्षण नीति जिसने बड़े सामाजिक और आर्थिक संरचना में सुधार लाने के लिए अमेरिकी सामाजिक नीति की सकारात्मक कार्रवाई से महत्वपूर्ण अवधारणा ली है। इस आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय सामाजिक संरचना के साथ मौजूद सामाजिक असमानता और भेदभाव को मिटाना है। इस संदर्भ में, सामाजिक असमानता के साथ–साथ विभिन्न सामाजिक मूल्यों की रूढ़िवादिता के सवाल पर कई उपाय किए गए हैं। लेकिन बाद में, जातिगत आरक्षण के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों से समाज के भीतर यह सामान्यीकृत हो जाता है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक उत्थान के लिए नौकरियों में अवसर देता है। यह वास्तव में नीति निर्माताओं के सामने चुनौती है जो भारतीय समाज और इसके विरोधाभासों के विषय में इसकी प्रकृति को समझने के लिए एक विस्तार क्षेत्र को उजागर करते हैं। इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर ऐसी नीतियों का कार्यान्वयन न केवल नीति के लिए बल्कि सरकार के लिए भी एक चुनौती है।

इसी प्रकार भारतीय समाज में लैंगिक प्रश्नों की अपनी जटिलताएँ हैं, पितृसत्ता जिसे महिलाओं के शोषण के मूल कारण के रूप में जाना जाता है। कई विद्वानों ने कहा है कि पितृसत्ता की अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ें है जो अभी भी अपनी संरचना और सांस्कृतिक संबंध बनाए हुए है। ये धार्मिक रूप से स्वी.त और वैचारिक रूप से समर्थित संस्थान दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह पूरे भारतीय समाज में मौजूद हैं। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान विभिन्न सामाजिक सुधार हुए जिन्होंने महिलाओं के लिए एक नई सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति लाने की चेष्टा की। वर्ग एक सामाजिक श्रेणी है जो आय पर आधारित है। हमारे समाज में वर्गीय असमानता सामाजिक श्रेणियों में व्यापक रूप से फैली हुई है जैसे लिंग, जातीयता, जाति आदि, राजनीतिक अध्ययन में वर्ग आधारित सामाजिक स्थिति सभी पहलुओं में शासक से संबंधित है।

1.6 वैश्वीकरण, राज्यतन्त्र और समाज

वैश्वीकरण की प्रक्रिया कोई नई घटना नहीं है, लेकिन प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ, इंटरनेट और तीव्र परिवर्तन ने वैश्वीकरण का एक नया चरित्र दिया है जिसमें वैश्विकता के साथ–साथ वैश्विक संस्कृति के खिलाफ प्रतिरोध भी है। इसका परिणाम रूढ़िवादी आंदोलन के के रूप में हुआ है जो विकास के पारंपरिक रूपों की रूढ़िवादी जड़ों की ओर लौटने के लिए हाशिए के लोगों के बीच एक भावना को उत्पन्न करता है। हम इसे योग, तीर्थयात्रा और आयुर्वेद के मर्सरीकरण के रूप में भी देख सकते हैं। यह कहा जाता है कि व्यापार और प्रवास में उभरी नई वैश्विक प्रवृत्तियों के साथ सरकार का स्थान सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रवादी विचारधाराओं के की भी आवश्यकता है।

एंथनी गिड्डन्स (1990) ने सुझाव दिया है कि आधुनिकता का बड़ा प्रभाव वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के विभिन्न प्रकारों और स्वरूपों के साथ, समय और स्थान ने केवल सामाजिक जीवन को बल्कि सांस्कृतिक प्रथाओं को भी पुनः परिभाषित किया है। इसे समय और स्थान का सुदुरिकरण कहा जाता है। गिड्डन्स के अनुसार बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता वैश्वीकरण है। यह परस्पर निर्भरता सामाजिक और आर्थिक संबंधों में निहित है।

वैश्वीकरण की यह प्रक्रिया ने राज्य और उसके सभी कार्यात्मक उपकरणों की भूमिका को भी पुनर्परिभाषित किया है और विकास के मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से परिलक्षित होता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया आर्थिक विकास पर आधारित नीति के नव उदारवादी विचार का परिणाम है। इससे शासन का स्वरूप भी बदल गया है। हम इसे नीतियों और कार्यक्रमों में गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) की बढ़ती भूमिका में देख सकते हैं। दूसरी तरफ वैश्वीकरण ने स्थानीय बाजार और सामाजिक परंपराओं को आधुनिक बाजार और सांस्कृतिक प्रथाओं द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए आक्रामक प्रयास किया। दूसरी तरफ, इसने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के हर मुद्दे पर एक वैश्विक संपर्क दिया है। ऐसा हम जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार के मुद्दों के मामले में देख सकते हैं।

भारत में केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में कई विकास कार्यक्रमों में, यह देखा गया है कि गरीबी, पलायन, रोजगार और महिला शोषण और अल्पसंख्यक मुद्दों पर वैश्विक पैमाना बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

यहां हम इसे शासन के बदलते स्वरूप में देख सकते हैं, जिसमें प्रशासन के वे स्वरूप भी शामिल हैं जो अब प्रबंध न होकर वैश्विक एजेंसियों द्वारा सुझाई गई नीति और कार्यक्रमों

के समन्वयक हैं। हालांकि यह दुनिया भर में विकासात्मक नीतियों से जुड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह पुराने सामाजिक प्रश्नों से निपटने के बजाय आर्थिक विकास के पक्ष में अधिक है। इसलिए, भारत के विभिन्न हिस्सों में चल रहे कई मानवाधिकार आंदोलनों ने स्थानीय संसाधनों को बड़े और बहुराष्ट्रीय निगमों से बचाने के लिए मजबूत और उग्र संघर्ष का नेतृत्व किया।

1.7 सारांश

इस अध्याय ने राज्यतन्त्र और समाज के मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। राज्यतन्त्र और समाज न केवल नीति कार्यक्रम और शासन के साथ जुड़ा हुआ है, अपितु यह मुद्दों को सुलझाने के प्रति उनके अधिकारों और राज्य की जिम्मेदारी के संघर्ष के साथ भी जुड़ा हुआ है। औपनिवेशिक काल के बाद के काल में शासन के स्वरूप में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यहां समाज न केवल गरीब, अनपढ़ और खराब बुनियादी ढांचे के साथ रहता है, अपितु इसकी रूढ़िवादी सामाजिक परंपराएं भी हैं जो सामाजिक प्रगति का मुख्य अवरोध हैं। हम इसे जातिवाद, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, जातीय समुदाय आदि में देख सकते हैं हालांकि भारत की स्वतंत्रता के बाद, लोगों के जीवन को बदलने के लिए कई कार्यक्रम शुरू हुए, लेकिन वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहे। 1991 के बाद के युग ने शासन के नए चरित्र की शुरुआत की जो निजी कार्यकर्ताओं के लिए अधिक सहयोगी है जो प्रशासक को सीईओ बनाते हैं। नीतियों और कार्यक्रम की धारणा बदलती रहती है, एक तरफ इसका वैश्विक चरित्र है दूसरी तरफ उनकी परंपरा और स्थानीय संसाधनों के लिए तीव्र भरसक संघर्ष समकालीन घटना है जो राज्यतन्त्र और समाज के बीच संबंधों का मार्गदर्शन कर रही है।

1.8 अन्य उपयोगी पुस्तकें

ए. कोहली (सं.), इंडियाज डेमोक्रेसी, प्रिंसटनरू प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस

ए.शर्मा और ए गुप्ता (सं.), 2006. द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द स्टेटः ए रीडर, ऑक्सफोर्ड ब्लैकवेल

बार्धन, पी. 1984, दा पॉलिटिकल इकनोमि ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ऑक्सफोर्डः ब्लैकवेल

बॉटमोर. 1979. पॉलिटिकल सोशियोलॉजीः लंदन. हचिंसन

बॉटमोर टी.बी.1971, सोशियोलॉजीः अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, ब्लैकी, बॉम्बे

1.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

i) लोगों की विभिन्न गतिविधियों का समन्वय और हितों के टकराव से निकलने वाले संघर्ष का समाधान सामाजिक संबंधों की एक क्रमवार व्यवस्था के लिए दो आवश्यकताएं हैं।

ii) एक राजनीतिक प्रणाली शक्ति या उसके विभिन्न अभिव्यक्तियों के अभ्यास के इर्दगिर्द आयोजित व्यक्तियों या समूहों के बीच सामाजिक संबंधों की एक प्रणाली को संदर्भित करती है।

iii) शक्ति वांछित प्रभावों को प्राप्त करने की क्षमता है। इसका तात्पर्य किसी भी व्यक्ति या समूह या संगठन पर दूसरों के कार्य पर पड़ने वाले प्रभाव से है। प्राधिकरण शक्ति का वैधीकरण है। दोनों अवधारणाओं का उपयोग राजनीति के संदर्भ में किया जाता है।

iv) राजनीति के प्रति एक सीमित .ष्टिकोण एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के संगठन के लिए राजनीतिक संबंधों की परिभाषा को परिभाषित करता है। यह संगठन भी शारीरिक बल के अनुमोदन पर आधारित है। यह प्रतिबंधित .ष्टिकोण ऐसे राजनीतिक संबंधों पर ध्यान देने में विफल है, जो क्षेत्रीय रूप से परिभाषित नहीं हैं।

बोध प्रश्न 2

i) सोसाइटी का तात्पर्य ऐसे सामाजिक संबंधों से है जो परस्पर जुड़े हुए हैं। यह सामाजिक संगठन की एक श्रेणी भी है, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं जैसे कि रक्तसंबंध, परिवार, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समुदाय और संघ शामिल हैं।

ii) एक राष्ट्र उन लोगों के समूहों को संदर्भित करता है जिन्होंने संस्कृति, धर्म, भाषा और राज्य की सामान्य पहचान के आधार पर एकजुटता विकसित की है।

iii) एक राज्य एक राजनीतिक संघ को संदर्भित करता है, जो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, गैर–स्वैच्छिक सदस्यता और एक संविधान द्वारा चरितार्थ होता है। यह अपने सदस्यों पर सत्ता की वैधता का दावा भी करता है।

1.10 शब्दावली

राष्ट्र – लोगों का एक समूह जो राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता के आधार पर खुदकी पहचान करता है

राष्ट्र निर्माण – राष्ट्रीय पहचान के विकास की प्रक्रिया

राजनीतिक तंत्र – समाज की वे व्यवस्थाएँ, औपचारिक या अनौपचारिक, जो सत्ता पर आधारित होती हैं और जिनमें आधिकारिक निर्णय किए जाते हैं

राज्य – एक राजनीतिक संघ जो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र, गैर–स्वैच्छिक सदस्यता, सदस्यों के निश्चित अधिकारों एवम् कर्तव्यों और शक्ति के वैध उपयोग पर एकाधिकार द्वारा चरितार्थ होता है

संदर्भ ग्रंथ

ए. कोहली (सं.), इंडियाज डेमोक्रेसी, प्रिंसटन रू प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस

ए.शर्मा और ए. गुप्ता (सं.), 2006. द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द स्टेटः ए रीडर, ऑक्सफोर्डः ब्लैकवेल

बार्धन, पी. 1984.दा पॉलिटिकल इकोनोमी ऑफ डेव्लोप्मेंट इन इंडिया भारत में राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विकास, ऑक्सफोर्डः ब्लैकवेल

बॉटमोर टॉम। 1979. पोलिटिकल सोशियोलॉजीः लंदन. हचिंसन

बॉटमोर टी.बी.1971, सोशियोलॉजीः अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, ब्लैकी, बॉम्बे

चेटर्जी पार्थ. डेमोक्रेसी एंड इकॉनमी ट्रांस्फोमेशन इन इंडिया, इकॉनमीक एंड पॉलिटिकल वीक्ली, सं.43, संख्या 16 (अप्रैल.199, 2008) .प्रष्ठ.53–62.

फोर्ट्स और ई.ई.ईवंस प्रिचर्ड (सं.) 1940. एफ्रिकन पॉलिटिकल सिस्टम, लंदनः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

फुलर और बेनीडेस. 2000. एवरी डे स्टेट एंड सोसाईटी इन मॉडर्न इन इंडिया. दिल्ली. सोशियल साइंस प्रेस

कोठारी. रजनी. 1970. कास्ट इन इन्डियन पॉलिटिक्स. हैदराबादः ओरिएंट लॉन्गमैन.

एल रुडोल्फ और एस. रुडोल्फ, 1987. इन पर्स्यूट ऑफ लक्ष्मीः दा पोलिटिकल इकॉनमी ऑफ दा इन्डियन स्टेट. शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस.

लिसपेट एस.एम.एड., 1969. पॉलिटिक्स एंड सोशल साइंस, न्यूयॉर्क, ओ यू पी.

ल्यूकस, स्टीवन। 2006, पावरः ए रेडिकल व्यू, सं2., हैम्पशायररू पालग्रेव

एम.जे. श्वार्ट्ज (सं.), लोकल लेवल पॉलिटिक्सः सोशल एंड कल्चुरल पर्सपैक्टिव, लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस, प्रष्ठ .281–94.

मैकफर्सन, सी.बी. 1966. द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ऑक्सफोर्डः क्लेरेंडन प्रेस।

मायर्डल गुन्नार, 1972। एशियन ड्रामाः एन इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशंस, लंदनः एलन लेन।

ओमन, टी. के. नेश्नैलिती, 1997. एथनिसिटी एंड सिटीजनशिप, लंदन, पोलिटी

सान्याल कल्याण, 2007. रीथिंकिंग कैपिटलिस्ट डेवलपमेंटः प्रिमिटिव एक्युमुलेशन, गोवेर्नमेंटालिटी एंड पोस्ट कॉलोनियल कैपिटलिज्म, नई दिल्लीः रूटलेज।

सेन, अमरत्य. 999. डेवलेपमेंट एज फ्रीडम, नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

शाह घनश्याम, 2001. दलित आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स, दिल्लीः सेज

वेबर मैक्स। 1947. दा थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनोमिक आर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्कः दा फ्री प्रेस

..... । 1978, इकोनोमी एंड सोसाईटीः एन आउटलाइन ऑफ इंटरप्रिटेटीव सोशियोलॉजी, बर्केली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस

इकाई 2 राजनीतिक समाजशास्त्रः प्रकृति और क्षेत्र

संरचना

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 राजनीतिक समाजशास्त्र का उद्भव

2.3 राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ

2.4 राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र

2.5 सारांश

2.6 उपयोगी पुस्तकें

2.7 शब्दावली

2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद, आप समझ सकेंगेः

- राजनीतिक समाजशास्त्र के उद्भव के विषय में;
- राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ;
- राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र को।

2.1 प्रस्तावना

इस खंड के पिछली इकाई में राज्यतंत्र और समाज पर चर्चा की गई है। इस इकाई में हम राजनीतिक समाजशास्त्र के उद्भव, अर्थ और क्षेत्र पर चर्चा करेंगे।

राजनीतिक समाजशास्त्र समकालीन समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक उप क्षेत्र है। यह राजनीतिक संगठन और संस्थानों, सत्ता और प्राधिकार, और शासक और शासित के व्यवहार पर केंद्रित होता है। यह एक व्यापक उपक्षेत्र है जो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र को जोड़ता है। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है; और राजनीति के समाजशास्त्र और राजनीतिक समाजशास्त्र के बीच के अंतर्संबंध को भी। स्मेलसर ने वैज्ञानिक अनुशासन के लिए चार मानदंडों, जैसे आश्रित घटक, स्वतंत्र घटक, तार्किक क्रम (कारण प्रभाव संबंध, मॉडल और सैद्धांतिक फ्रेम वर्क), और अनुसंधान विधि प्रस्तावित किए। उन्होंने समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच अंतर बताया है। समाजशास्त्र को उस विषय के रूप में परिभाषित किया गया है जो "विभिन्न व्याख्यात्मक चरों के लिए सामाजिक संरचनात्मक परिस्थितियों का चयन करता है।" जबकि राजनीति विज्ञान वह अनुशासन है जो "व्याख्या के लिए राजनीतिक संरचनात्मक परिस्थितियों का चयन करता है। बेंडिक्स और लिपसेट के अनुसार, 'राजनीतिक विज्ञान

* डा. विनोद यादव द्वारा लिखित

राज्य से शुरू होता है और समाज पर उसके प्रभाव का अध्ययन करता है जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र समाज से शुरू होता है और राज्य पर उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। यह अंतर राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र को समझने में सहायक है।

राजनीतिक समाजशास्त्र का इस्तेमाल 'राजनीति के समाजशास्त्र' के पर्याय के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इतना ही नहीं है। जियोवानी सार्तोरी राजनीति के समाजशास्त्र और राजनीतिक समाजशास्त्र के बीच भेद करते हैं। राजनीति के समाजशास्त्र की तुलना में राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है। राजनीति के समाजशास्त्र की दृष्टि संकीर्ण है। यह घटना के एकांगी रूप का अध्ययन करता है और शेष बचा रहा जाता है।

राजनीति का समाजशास्त्र समाजशास्त्र का एक उप क्षेत्र है। यह राजनीति का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन है। यह घटना को आश्रित घटक के रूप में मानता है और अंतर्निहित सामाजिक घटना को व्याख्यात्मक घटक के रूप में। यह गैर राजनीतिक तत्त्वों का अध्ययन करता है जैसे कि लोग राजनीतिक जीवन में जो व्यवहार अपनाते हैं तो क्यों अपनाते हैं। जबकि, राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक घटना को सामाजिक निर्धारकों से जोड़कर राजनीतिक घटना को समझने का एक प्रयास है। यह राजनीति और समाज, सामाजिक संरचनाओं और राजनीतिक संरचनाओं और सामाजिक व्यवहार और राजनीतिक व्यवहार के बीच संबंधों का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार, समाजशास्त्रीय और राजनीतिक–तार्किक दृष्टिकोण एक विशेष बिंदु पर आकर मिलते हैं। इसमें राजनीतिक कारण शामिल होते हैं कि लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं।

जियोवानी सार्तोरी के अनुसार, "राजनीतिक समाजशास्त्र एक अंतर्विषयक मिश्रण है जो सामाजिक और राजनीतिक व्याख्यात्मक घटकों का सम्मिश्रण है।" यह समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच का सेतु है। यह समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच दोतरफा संबंधों पर विश्वास करता है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक घटकों पर समान बल दिया जाता है। आइए हम राजनीतिक दलगत प्रणाली का उदाहरण लें। यहाँ राजनीतिक समाजशास्त्र केवल सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के प्रतिबिंब के रूप में पार्टी प्रणाली के काम की व्याख्या ही नहीं करता है, बल्कि समाज पर दलगत प्रणाली के प्रभाव का भी मूल्यांकन करता है।

2.2 राजनीतिक समाजशास्त्र का उद्‌भव

'राजनीति' अरस्तू का प्रसिद्ध कार्य था, जिसने संकेत दिया कि राजनीति ग्रीक शब्द 'पॉलिस' से ली गई है जिसका अर्थ है शहर–राज्य, जो राज्य, सरकार और प्रशासन से संबंधित है। ग्रीक सिद्धांत के उत्पत्ति के अनुसार, राजनीतिक विज्ञान वास्तव में सैद्धांतिक व्याख्याओं, वर्णनात्मक विचारो, अनुमानित विकल्पों, अमूर्त और मूल्य–आधारित विचारों या अन्य शब्दों में, एक 'मानक अध्ययन' पर आधारित राजनीतिक दर्शन था। राजनीतिक समाजशास्त्र की उत्पत्ति एलेक्सिस डी टोकेविल, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खीम और मैक्स वेबर के लेखन सहित अन्य लेखकों के लेखनी से पता लग सकता है, हालाँकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजशास्त्र के भीतर केवल एक अलग उपक्षेत्र के रूप में उभरा। 1950 और 1970 के दशक के कई ऐतिहासिक कार्य, वर्ग, धर्म, नस्ल/जातीयता के प्रभाव जैसे व्यक्ति और समूह–आधारित राजनीतिक व्यवहार पर शिक्षा के सूक्ष्म प्रश्नों पर केंद्रित थे। 1970 के शुरुआती दशक में, राजनीतिक समाजशास्त्री स्रोतों की समझ, क्रांति के परिणामों, राजनीतिक परिणामों को आकार देने में राजनीतिक संस्थानों की भूमिका और राज्य के विकास में व्यापक स्तर पर तुलनात्मक–ऐतिहासिक अध्ययनों जैसे वृहत विषयों

की ओर तेजी से बढ़े। वर्तमान समय में छोटे और बड़े स्तर के विद्वान राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र को अक्सर विचलन, अमूर्त और खंडित माना जाता रहा है, फिर भी राजनीतिक समाजशास्त्रियों द्वारा विशेष रूप से शोध किए गए समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के विकास में प्रासंगिक विषयों के कारण इसे समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र भी मानते हैं।

राजनीतिक समाजशास्त्र के इतिहास और विकास को कम से कम चार भागों में बाँटा जा सकता है। पहला, शास्त्रीय काल है। इसका अस्तित्व ग्रीक और रोमन काल के दौरान था जब मनुष्य को मुख्य रूप से एक राजनीतिक पशु समझा जाता था। बाद में, पवित्र रोमन साम्राज्य के दौरान, उन्हें विशुद्ध रूप से धार्मिक शब्दों में पुनर्परिभाषित किया गया और भगवान का एक अंश माना गया। प्लेटो, अरस्तू, सिसेरो, सेंट औगास्ताइन और सेंट थोमस एक्विनास जैसे राजनीतिक दार्शनिक राजनीतिक समाजशास्त्र के शास्त्रीय काल के प्रतिनिधि हैं।

दूसरी प्रवृत्ति पुनर्जागरण काल के दौरान देखी जा सकती है। इसमें दो अलग–अलग मान्यताओं के राजनीतिक दार्शनिकों के बीच एक महान बहस शामिल थी। पहली मान्यता वाले श्रेणी में लॉक, मोंटेस्क्यू, रूसो थे, बाद में सेंट–साइमन, कॉम्टे और कार्ल मार्क्स शामिल थे। उनके अनुसार, समाज और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। दूसरी मान्यता को मानने वालों में मैकियावेली, हॉब्स, बर्क, हेगेल, बोनाल्ड और मैस्ट्रे जैसे दार्शनिक शामिल थे, जो समाज और राजनीति में भेद नहीं करते थे और पारंपरिक राजतंत्र और चर्च के आधिपत्य और वैधता के पक्षधर थे। इसके अलावा, मैक्स वेबर, मैकाइवर और अन्य विद्वानों का योगदान राजनीतिक समाजशास्त्र के उद्‌भव के लिए अद्वितीय रहा।

राजनीतिक समाजशास्त्र के उद्‌भव में तीसरी प्रवृत्ति समाज में कुलीनों की भूमिका से संबंधित है। अभिजात वर्ग (elite) शब्द को सत्रहवीं शताब्दी में उत्कृष्टता का एक मानक के रूप में स्वीकार किया गया। बाद में, यह बेहतर सामाजिक समूहों, जैसे अत्यधिक सफल सैन्य इकाइयों और अभिजात वर्ग के उच्च पदों के रूप में विस्तारित किया गया। इसका व्यापक प्रयोग दो इतालवी समाजशास्त्रियों, परेतो और मोस्का द्वारा उपयोग किया गया। आम तौर पर, कुलीन सिद्धांतकारों ने तर्क दिया कि इतिहास विचारों, जनता या चुपचाप काम करने वाली शक्तियों द्वारा नहीं बल्कि समय–समय पर स्थान परिवर्तन करने वाले व्यक्तिगत रूप से छोटे समूहों द्वारा बनाया गया था। संभ्रांत सिद्धांतकारों का मानना है कि सम्पूर्ण इतिहास में समाज में हमेशा अल्प संख्या वाले शासकों का एक अलग स्थान रहा है और महत्वपूर्ण संसाधनों एकाधिकार के कारण वे प्रभावी संगठन और नियंत्रण को बढ़ाने में सक्षम थे। उन संसाधनों में सैन्य बल, धार्मिक शासन, आर्थिक वर्चस्व, या राजनीतिक शक्ति थे जिसपर विभिन्न समाज का नियंत्रण समय–समय पर बदलता रहता था।

राजनीतिक समाजशास्त्र के उद्‌भव में चौथी प्रवृत्ति समकालीन काल है। यह काल अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्लेषणात्मक है। विकास के प्रमुख सिद्धांत के निर्माण के साथ–साथ, यह समाज और राजनीति से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रामाणिक सामान्यीकरण पर बल देता है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के सबसे प्रमुख विद्वानों में लिप्सेट, ग्रीर, इंकल्स, मूर, कोर्नहौसर, मिल्स, हंटर, जानोविट्‌ज, लेजरफील्ड, ईसेनस्टेड, सेल्निक, रोक्कन, गुसफील्ड और मैक्रै जैसे प्रमुख राजनीतिक समाजशास्त्री हैं। ये राजनीतिक समाजशास्त्री रचनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं और उन्होंने इसे परिश्रम से परिपक्व सामाजिक वैज्ञानिक विषय के रूप में बढ़ाया है।

2.3 राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ

समाजशास्त्री राजनीतिक समाजशास्त्र के सटीक अर्थ पर सहमत नहीं हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र के अर्थ से संबंधित परस्पर विरोधी धारणाएँ निम्नलिखित हैं:

1. यह राजनीतिक समाजशास्त्र को राज्य का विज्ञान मानता है। राजनीतिक समाजशास्त्र को परिभाषित करने के लिए राज्य के विज्ञान को सामाजिक विज्ञानों के रूप में विभाजित करना है, जो सामाजिक प्रकृति के अध्ययन पर आधारित है। ग्रीर और ऑरलियन्स, जेलिनक और मार्सेल प्रेलोट इस धारणा के नजदीक हैं।

2. राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राजनीति के बीच अंतःक्रिया प्रक्रिया है। बेंडिक्स और लिपसेट का मानना है, "राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होकर समाज को प्रभावित करने वाले कारणों का मूल्यांकन करता है जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र समाज से शुरू होकर राज्य को प्रभावित करने वाले प्रकिया का मूल्यांकन करता है।"

3. मौरिस डावरगर द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक समाजशास्त्र अधिक आधुनिक है। इनके अनुसार, राजनीतिक समाजशास्त्र सभी मानव समाजों (राष्ट्रीय समाजों सहित) में, सरकार, आधिपत्य और सत्ता का विज्ञान है। अनेक समकालीन लेखक राजनीतिक समाजशास्त्र के इस परिभाषा को कुछ संशोधनों के साथ मानते हैं; उनमें विशेष रूप से मैक्सवेबर, रेमंड आरोन, जॉर्ज वेडेल, जॉर्ज बर्ड्उ और मौरिस डावरगर हैं।

4. राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान का समन्वय है, जो विशेषज्ञता पर आधारित है। इस प्रकार, राजनीतिक समाजशास्त्र स्थापित जनक विषयों समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के अंतःविषय पूर्वज के रूप में माना जा सकता है और इन दो क्षेत्रों के बीच के अन्तर्संबद्ध को दिखाता है। यह अधिक व्यवस्थित है जिसका उद्देश्य विभिन्न अंतर्विषयक सीमाओं के बीच सेतु निर्माण करना है।

2.4 राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र

एक विषय के रूप में, राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच का मिलन बिंदु है: यह राजनीति तथा राजनीतिक विज्ञान दोनों से संबंधित विषयों पर चिंतन करता है। हालाँकि, यह राजनीति विज्ञान से कई मायनों में भिन्न है। राजनीतिक समाजशास्त्री राजनीतिक संस्थानों को अपने अधिकार में लेने के बजाय राजनीतिक संस्थानों और अन्य सामाजिक संस्थानों और समाज के बीच के संबंधों पर सामान्यतः जोर देते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र का व्यापक और ऐतिहासिक दायरा भी है। इस अनुशासन के केंद्र में मानव समाजों के भीतर होने वाली राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र आपसी संवाद के आधार पर राज्य और समाज के बीच संबंध और अंतिम रूप से सभी राजनीतिक प्रक्रियाओं के रूप में सत्ता से संबंधित है। राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के सामाजिक आधार (सामाजिक पहचान सहित), सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण (राजनीतिक संस्कृति सहित), राजनीतिक संबंध और प्रतिद्वंद्विता की प्रक्रिया (चुनाव और विरोध राजनीति सहित) के गठन के सामाजिक आधार के अध्ययन, राजनीतिक संस्थानों (लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्यों सहित) में बदलाव, और रखरखाव से संबंधित है। यह अध्ययन का अपेक्षाकृत नया क्षेत्र रहा है जो अभी भी विकसित हो रहा है। विभिन्न राजनीतिक समाजशास्त्री इस क्षेत्र को अलग–अलग तरीकों से परिभाषित करते हैं।

ग्रीर और ऑरलियन्स के अनुसार, "राजनीतिक समाजशास्त्र राज्य की संरचना, प्रकृति और वैधता की शर्तों से संबंधित है; शक्ति के एकाधिकार की प्रकृति, और उनके संबंधित राज्यों के साथ लोगों के संबंध राजनीतिक समाजशास्त्र के कार्यक्षेत्र में आते हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य, सत्ता, आम सहमति और वैधता, भागीदारी और प्रतिनिधित्व और आर्थिक और राजनीतिक विकास के बीच संबंध के साथ राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र का विषय है।

लिपसेट और बेंडिक्स के अनुसार, समुदाय और उनके राष्ट्र, राजनीतिक मत व्यवहार और आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण, राजनीतिक आंदोलनों की विचारधारा और हित समूह राजनीतिक समाजशास्त्र से संबंधित है। इन क्षेत्रों के साथ–साथ, राजनीतिक समाजशास्त्र का बहुत बड़ा दायरा है क्योंकि यह सामाजिक संबंधों के सभी पहलुओं की दृष्टि से सत्ता की राजनीति का अध्ययन करता है।

राजनीतिक समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की दृष्टि के अनुसार राज्य की शक्ति, अधिकार और वैधता का अध्ययन करता है। इसमें नौकरशाही, हित समूह, लोगों की राजनीतिक भागीदारी, संघर्ष और संघर्ष–समाधान, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण, निर्णय लेने, राजनीतिक आंदोलनों, सामाजिक परिवर्तन, हिंसा और क्रांति और कुछ अन्य क्षेत्रों की गतिविधियां शामिल हैं।

मौरिस ड्यूवरगर का मानना है कि राजनीतिक समाजशास्त्र शक्ति और अधिकार के दो पहलुओं के इर्द–गिर्द केंद्रित है, अर्थात् उत्पीड़नकर्ता और एकीकरणकर्ता। उनके अनुसार, इसके कार्यक्षेत्र में शामिल हैः राजनीतिक संरचनाएँ जिनमें प्रतिपक्षी और एकीकरण की द्वंद्व, समाज में संघर्ष और एकीकरण के कारणय और संघर्षों को हल और एकीकृत करने के तरीके। मौरिस ड्यूवरगर मानते हैं किः (i) राजनीतिक समाजशास्त्र प्रत्येक मानव समूह में निहित शक्ति का अध्ययन है, न कि केवल राष्ट्र–राज्य में। इसलिए, इन समूहों में से प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष और एकीकरण का संरचना और एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक संरचनाओं में भौतिक संरचनाएं (भौगोलिक और जनसांख्यिकीय), और सामाजिक संरचनाएं (तकनीकी कौशल, संस्थान और संस्कृतियां) शामिल हैं, (ii) राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक विरोधियों के होने के कारणों का विश्लेषण करता है। राजनीतिक विरोध व्यक्तियों के साथ–साथ समूहों के बीच भी हो सकते हैं; (iii) राजनीतिक समाजशास्त्र संघर्ष और एकीकरण का भी अध्ययन है। संघर्ष स्वाभाविक रूप से एकीकरण की ओर विरोध, विकसित होकर, आत्म–उन्मूलन और बाद में सामाजिक सद्भाव की ओर अग्रसर होता है। इसलिए राजनीतिक समाजशास्त्र के दायरे में राजनीतिक संरचनाएं, राजनीतिक विरोधियों के अस्तित्व के कारण और उनके एकीकरण तक शामिल हैं।

चार्ल्स टिली ने राष्ट्र निर्माण को सामूहिक गतिविधि से जोड़ा, जिसका सीधा प्रभाव नागरिकता की समझ पर पड़ा। यद्यपि वह राज्य निर्माण प्रक्रिया को ऐसा मानते हैं जो संभावित रूप से अन्य सामाजिक शक्तियों से मुक्त है। टिली (1975, 1986) इस सामूहिक गतिविधि को ऐतिहासिक रूप से जनता की गतिशीलता, एकत्रीकरण और समझौता द्वारा केन्द्रीय एवं संसाधन–लालची राज्य के बीच एक संबंध के रूप में विश्लेषण करती हैं। सामूहिक गतिविधियां राज्य निर्माण, पूँजीवादी विस्तार, शहरीकरण और जबरदस्ती (विशेष रूप से युद्ध) की प्रक्रियाओं के अनुपात व्यापक रूप से बदलती हैं। इस प्रकार, जनता द्वारा अपने हितों में काम करने के तरीकों के कारण राष्ट्रीय राज्य निर्माण में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआः चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए निर्णयों पर अधिक निर्भरता थी, इसलिए आम नागरिक के हितों पर केंद्रित राजनीतिक शक्तियों के प्रासंगिक स्तर बिखरे हुए थे जिसके लिए सामूहिक गतिविधि हेतु नए साधनों और नए लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। एक

तरफ, व्यक्तियों की क्षमता और रचनात्मकता में उनकी गतिशीलता को निर्धारित करना चाहता है; और, दूसरी तरफ, संरचनात्मक बाधाएं जो संभावनाओं को सीमित करती हैं – या, दूसरे शब्दों में, सामूहिक गतिविधि को बाधित करते हैं।

इस प्रकार, उलरिच बेक (1992, 1999) उदाहरणार्थ दावा करता है कि वैश्विक प्रक्रियाएं आधुनिकता का खंडन करती हैं, जिसकी प्रेरक शक्ति (व्यक्तिवादिता) सामूहिक अस्मिता के निर्माण में संकट पैदा करता है जैसे कि एक राष्ट्रीय समाज द्वारा स्थापित तरीका, कोड और नियमों का विघटन। दूसरे शब्दों में, राजनीति विशेष रूप से संसदों, दलों, यूनियनों आदि जैसे संस्थानों में नहीं पाई जाती। यह अब निजी जीवन के केंद्र में पाई जाती है, क्योंकि निजी जीवन के संचालन का सूक्ष्मरूप वैश्विक समस्याओं से संबंधित है (जैसे पर्यावरण का मुद्दा)। इस प्रकार, राष्ट्र–राज्य संरचना में राजनीति अब राजनीतिक, भूराजनीति या वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त समाज के के लिए प्रारंभिक बिंदु नहीं है।

अलग–अलग दृष्टिकोण (डेलेंटी और कुमार, 2006; स्मिथ, 2010 [2001]; यंग इत्यादि, 2007) राष्ट्र और राष्ट्रवाद की दृढ़ता को सधे हुए हित के अनुसार सामाजिक घटना के रूप में, पहले व्यक्तिपरक समुदाय और बाद में एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से दोनों सामाजिक आंदोलनों और राज्यों के राजनीतिक एजेंडे को सामाजिक शक्ति स्वीकार करता है। राजनीतिक संस्कृति पर किए गए अध्ययनों में, समाजीकरण प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहार के बीच संबंध भी प्रमुख हो जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि सहभागियों के उत्तर सामाजिक स्थितियों के अनुसार विषयवार रूप से दिए गए हैं या नहीं।

राजनीतिक समाजशास्त्र अनुसंधान का एक अन्य विषय है, जो राज्य/समाज संबंधों के साथ सामाजिक परिवर्तन के सैद्धांतिक मुद्दे और सामाजिक आंदोलनों को सीधे तौर पर स्पष्ट करता है। सामाजिक आंदोलनों (अलोंसो, 2009) की व्याख्या करने वाली कम से कम तीन प्रमुख सैद्धांतिक रेखाओं की पहचान की जा सकती है जो समकालीन चुनौतियों के सामने निर्मित हुए जिसमें सामूहिक एकता, हिंसा और अस्मितामूलक मुद्दों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना शामिल है। पहली सैद्धांतिक रेखा को तथाकथित संसाधन जुटाव सिद्धांत (मैकार्थी और जाल्ड, 1977) में व्यक्त किया गया है, जो सामूहिक भावनाओं के संदर्भ में सामूहिक एकता की व्याख्या के बजाय तर्क को महत्व देता है। दो अन्य प्रमुख सैद्धांतिक रेखाएं – तथाकथित राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत और नए सामाजिक आंदोलनों का सिद्धांत है जो क्रांति की संभावनाओं वाले मार्क्सवादी बहसों की उपज है। इस तथ्य के बावजूद कि पहला राजनीतिक परिवर्तन के सिद्धांत पर केंद्रित है, जबकि दूसरा एक सांस्कृतिक परिवर्तन दृष्टिकोण पर आधारित है, दोनों सामूहिक गतिविधि पर या तो निर्धारणवाद और अर्थवादी दृष्टिकोण के खिलाफ खड़े होते हैं या एक सार्वभौमिक ऐतिहासिक विषय पर विचार करते हैं, समष्टि–इतिहास पसंद करते हैं जो सामाजिक आंदोलनों की व्याख्या में राजनीति और संस्कृति का विश्लेषण करते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में, उदाहरण के लिए, सिडनी टैरो (1998), तर्क देते हैं कि जब 'राजनीतिक अवसर संरचना' में, यानी राजनीतिक वातावरण के औपचारिक और अनौपचारिक आयामों में, कोई परिवर्तन नहीं होते हैं तब सामाजिक समूहों के मांगों को पूरा करने के लिए राजनीति से इतर अभिव्यक्ति के माध्यम निर्मित किए जाते हैं। यह राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थानों के माध्यम से नागरिक समूहों बढ़ती मांगों की पारगम्यता के कारण हो सकता है, जो सत्ता में राजनीतिक गठबंधन के कुछ संकट; राज्य और समाज के बीच राजनीतिक संपर्क में परिवर्तन, विशेष रूप से विरोध आवाजों के दमन में कमी; और संभावित सहयोगियों (क्रिस्सी इत्यादि, 1995) की उपस्थिति के कारण हो सकता है।

विभिन्न हिस्सों के आपसी संघर्ष में एकता भी निर्मित होती है, जिनमें से एक हिस्सा राज्य पर नियंत्रण करता है और दूसरा समाज की ओर से बोलता है। चूँकि ऐसी स्थितियाँ परिवर्तनशील होती हैं, क्योंकि अभिनेता एक से दूसरे भूमिका में आते–जाते रहते हैं, इसलिए उन विश्लेषणों के पारंपरिक मान्यताओं को खारिज करना पड़ता है जो 'राज्य' और 'समाज' को दो सुसंगत और अलग–अलग संस्थाओं के रूप में परिभाषित करते हैं। ऐसे में, हालांकि सर्वोत्तम स्थिरता के साथ–साथ सजातीय परिप्रेक्ष्य को नहीं माना जाता है, लेकिन तथाकथित नए सामाजिक आंदोलनों के मुख्य सिद्धांतकारों में एक सामान्य विचार–विमर्श मिलता है– एलेन तुरीन, जुरगेन हैबरमास और अल्बर्टो मेलुच्ची। यदि, एक तरफ, उनमें से प्रत्येक विशद–ऐतिहासिक दृष्टिकोण और सामाजिक परिवर्तन और संघर्ष रूपों के बीच संबंध को बनाए रखता है, तो दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक आंदोलनों की प्रभावी सांस्कृतिक व्याख्या के विस्तार में भी शामिल होता है। इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्येक का अपना आधुनिकता का सिद्धांत होता है, वे कमोवेश एक ही मुख्य तर्क को साझा करते हैं, जो 20वीं शताब्दी के दौरान एक वृहत–संरचनात्मक परिवर्तन ने पूंजीवाद की प्रकृति को संशोधित किया होगा, जिसके केंद्र में अब औद्योगिक उत्पादन और कार्य नहीं होगा। श्रम संघर्षों को या तो लोकतांत्रिक संस्थानों के माध्यम से, जैसे कि अधिकार विस्तार आंदोलन, या पूंजीवादी संस्थान, जैसे वेतन बढ़ाकर कम किया गया और तकनीकी रूप से सूचना के नियंत्रण के माध्यम से प्रचलित सांस्कृतिक माहौल बनाया गया। निजी जीवन का राजनीतिकरण होगा। इसलिए वर्ग संघर्ष द्वारा अभिव्यंजनात्मक, प्रतीकात्मक और अस्मितामूलक आंदोलनों, जैसे कि नारीवाद, पर्यावरण और छात्रों के आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त होगा। वैश्विक प्रक्रियाओं की वृद्धि और राष्ट्र–राज्य से संबंधित संकट भी सामाजिक आंदोलनों के राजनीतिक समाजशास्त्र के लिए अवश्यम्भावी चुनौतियाँ हैं। राजनीति में राष्ट्रीय/स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय/वैश्विक स्तर के साथ–साथ इसके व्यवसायीकरण का, जो तथ्यतः विभिन्न पश्चिमी देशों में सामाजिक आंदोलनों एवं उद्यम संस्कृति का अधिग्रहण या सार्वजनिक/राज्य सेवाओं का नौकरशाही में हुए तीव्र बदलाव सामना करना आवश्यक है (रूट्स, 1996)। इसके अलावा, समकालीन विरोध प्रदर्शनों का स्वर और मुद्दे अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर अंतरराष्ट्रीय जनमत तक निर्देशित होते हैं। जातीय, धार्मिक, साम्यवादी और रूढ़िवादी संघों की हालिया लहर के कारण नए सामाजिक आंदोलनों और उत्तर–भौतिकवादी मुद्दों में आई कमी भी बहुत महत्वपूर्ण है।

'सिविल सोसाइटी' (अलेक्जेंडर, 1993) के विचार का फिर से उभरना और 'सार्वजनिक क्षेत्र' के बहसों के लिए जिम्मेदार मूल्य, राजनीतिक सिद्धांत के अधिक ऐतिहासिक झुकावों के लिए प्रासंगिक सैद्धांतिक विकल्पों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो मुख्य रूप से राष्ट्र–राज्य की समस्या पर केंद्रित होते हैं। इन विकल्पों (कोहेन और आरतो 1992) को अधिक से अधिक ऐतिहासिक समर्थन और व्यापकता प्रदान करने के प्रयास हुए हैं, भले ही उनके यूरोपीय विचारों की कड़ी आलोचना की जाती है (हैन और डन, 1996)। हर मामले में, यह सच है कि ये विकल्प राष्ट्र–राज्य से जुड़ी सामूहिक अस्मिता की समस्या के .ष्टिकोण से 'न्यूनतम' लगते हैं, जब तक वे यह सुझाव नहीं देते कि लोगों को मूल रूप से खुली और समान बहस के प्रक्रियात्मक नियमों को स्वीकार कर अपने व्यक्तिगत हितों को मानना चाहिए (एडर, 2003)। हालाँकि, शायद जो सबसे अधिक प्रासंगिक है, वह यह है कि 'सिविल सोसाइटी' और 'पब्लिक स्फीयर' के विचारों के इस पुनर्मूल्यांकन ने राज्य और समाज के बीच संबंधों के महत्वपूर्ण पुनर्निर्धारणों को आगे बढ़ाया है। इससे, कुछ मामलों में, राज्य और समाज के अलग–अलग विचारों की वापसी हो सकती है और इसलिए आगे चलकर राजनीतिक समाजशास्त्र की विशिष्टता पर केंद्रित अनुसंधान परंपरा स्थापित होगी।

बोध प्रश्न I

1. समाजशास्त्र के उद्‌भव की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. राजनीतिक समाजशास्त्र की सविस्तार व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.5 सारांश

इस इकाई में, हमने राजनीतिक समाजशास्त्र की उत्पत्ति और यह कैसे एक उप–अनुशासन बन गया है जो राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र को जोड़ता है का पता लगाने की कोशिश की है। हमने राजनीतिक समाजशास्त्र के अर्थ से संबंधित परस्पर विरोधी धारणा का पता लगाने का भी प्रयास और राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र विस्तार पर भी चर्चा की।

2.6 अन्य उपयोगी पुस्तकें

Anderson B. 1991. Imagined Communities. London: Verso.

Bendix R (1977 [1964]) Nation Building and Citizenship. Berkeley: University of California

Marshall T. H. 1950. Citizenship and Social Class and Other Essays. Cambridge: Cambridge University Press.

Mills, C. Wright. 1959. The Sociological Imagination. New York: Oxford University Press.

Nash, Kate. 2007. Contemporary political sociology: Globalization, politics, and power. Chichester, UK: Wiley-Blackwell.

2.7 शब्दावली

राष्ट्र–राज्य : राज्य का एक ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट रूप, जो यूरोप और अमेरिका में सत्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक विकसित हुआ और बीसवीं शताब्दी में विघटन के साथ दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गया, जो साझा सांस्कृतिक रिवाजों के अनुसार लोगों को एकीकृत करने का प्रयास करता है।

देशांतर : राष्ट्रीय सीमाओं से परे संबंधों या प्रक्रियाओं का जिक्र जो राष्ट्र–राज्य से बाहर हैं।

2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. राजनीतिक समाजशास्त्र का उद्भव एलेक्सिस डी टोकेविले, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खीम और मैक्स वेबर के लेखन से पता लगाया जा सकता है, लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केवल एक अलग इकाई के रूप में ही उभर पाया। चार प्रमुख प्रवृतियाँ हैं जो राजनीतिक समाजशास्त्र के इतिहास और विकास की विशेषता को दर्शाते हैं जैसे शास्त्रीय काल, पुनर्जागरण काल, अभिजात वर्ग की भूमिका और समकालीन काल।

2. यद्यपि समाजशास्त्रियों में राजनीतिक समाजशास्त्र के सटीक अर्थ को लेकर आम सहमति नहीं है और उनसे संबंधित कुछ परस्पर विरोधी धारणाएं भी हैं। इन धारणाओं में व्यापक रूप से राज्य के विज्ञान, समाज और राजनीति के बीच संवाद प्रक्रिया, सत्ता, सरकार और प्रभुत्व के बीच संवाद और समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के एकीकरण के रूप में राजनीतिक समाजशास्त्र पर चर्चा की गई।

3. राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र राज्य, सत्ता, सर्वसम्मति और वैधता, भागीदारी और प्रतिनिधित्व और आर्थिक और राजनीतिक विकास के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है। इन बिन्दुओं के मद्देनजर, राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत बड़ा है क्योंकि यह सामाजिक संबंधों के सभी पहलुओं के संबंध में सत्ता की राजनीति का अध्ययन करता है।

संदर्भ

Alexander JC (1993) The return to civil society. Contemporary Sociology 22(6): 797-803.

Anderson B (1991) Imagined Communities. London: Verso.

Balakrishnan G (ed.) (1996) Mapping the Nation. London: Verso.

Beck U (1996) The Reinvention of Politics: Rethinking Modernity in the Global Social Order. Cambridge: Polity Press.

Bendix R (1977 [1964]) Nation Building and Citizenship. Berkeley: University of California Press.

Bhabha HK (ed.) (1990) Nation and Narration. London:Routledge.

Braungart, Richard. 1981. "Political Sociology: History and Scope."Pp. 1-80 in Handbook of Political Behavior, edited by S. Long. New York: Plenum.

Calhoun C (2007) Nations Matter: Culture, History, and the Cosmopolitan Dream. New York: Routledge.

Delanty G and Kumar K (eds) (2006) The Sage Handbook of Nations and Nationalism. London: Sage.

Eder K (ed.) (2003) Collective Identities in Action: A Sociological Approach to Ethnicity. Aldershot: Ashgate.

Gupta D (1996) Engaging with events: The specifics of political sociology in India. Current Sociology 44(3):53-69.

Hann C and Dunn E (eds) (1996) Civil Society: Challenging Western Models. London: Routledge.

Marshall TH (1950) Citizenship and Social Class and Other Essays. Cambridge: Cambridge UniversityPress.

Mills, C. Wright. 1956. The Power Elite. New York: Oxford University Press.

_____. 1959. The Sociological Imagination. New York: Oxford University Press.

Nash, Kate. 2007. Contemporary political sociology: Globalization, politics, and power. Chichester, UK: Wiley-Blackwell.

Pugh , M. (1992). Women and the Women ' s Movement in Britain 1914 - 59 .London : Macmillan .

Rootes CA (1996) Political sociology in Britain: Survey of the literature and the profession. Current Sociology44(3): 108-132

Scott , A. (1990). Ideology and the New Social Movements . London : UnwinHyman .

Taylor , G. (1995). " Marxism . " In D. Marsh and G. Stoker (eds.), Theory and Methods in Political Science . London : Macmillan.

Tilly C (1975) Reflections on the history of European state-making. In: Tilly C (ed.) The Formation of National States in Western Europe. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Tilly C (1986) The Contentious French: Four Centuries of Popular Struggle. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Tilly C (1993) Contentious repertoires in Great Britain,1758-1834. Social Science History 17.

Tocqueville, Alexis de. 1945 [1835]. Democracy in America. New York: Vintage Books.

Weber, Max. 1947. The Theory of Social and Economic Organization. Translated by A. Henderson andT. Parsons. Glencoe, IL: The Free Press.

Sartori,Giovanni (1969) From the Sociology of Politics to political sociology,S.M.Lipset(edt) Social Science and Politics,Oxford University Press,London and New York

Rathore,L.S.(1986) "Political Sociology:Its Meaning,Evolution and Scope" .The Indian Journal of Political Science Vol.47,No.1(January-March1986) Political Science Association.